347

संख्या : 279 / XIII-II / 2013–26(05) / 2012

प्रेषक,

विनोद प्रसाद रतूड़ी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर निदेशक,
जलागम प्रबन्धन निदेशालय,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

कृषि एवं विपणन अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 27 सितम्बर, 2013

विषयः विश्व बैंक पोषित SLEM परियोजना (Sustainable Land Water and Bio-diversity Conservation and Management for Improved livelihoods in Uttarakhand Watershed Sector Project) के अन्तर्गत Final Impact Evaluation कार्य हेतु चयनित कंसलटेन्सी एजेन्सी को अवशेष कन्सल्टैंसी शुल्क के भुगतान / व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 218/XIII(2)/2012-26(05)/2012 दिनांक 20.11.2012, शासनादेश संख्या 01/XIII(2)/2013-26(05)/2012 दिनांक 04.02.2013 एवं आपके पत्र संख्या 513 / 10–26(SLEM Project-GEF) दिनांक 23.8.2013 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उक्तानुसार Final Impact Evaluation कार्य उक्त संस्था से कराए जाने के फलस्वरूप, उपरोक्त अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष अवशेष कन्सल्टेंसी शुल्क ₹ 13,43,166 / – (₹ तेरह लाख तैतालीस हजार एक सौ छियासठ मात्र) को वित्तीय वर्ष 2013–14 में आपके निवर्तन पर रखी गई धनराशि से व्यय / भुगतान किए जाने की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. उक्त स्वीकृति **Final Impact Evaluation** की ड्राफ्ट रिपोर्ट के आधार पर व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही है। अन्तिम आख्या उपलब्ध कराए जाने पर ही शेष धनराशि का नियमानुसार प्रस्ताव शासन के विचारार्थ उपलब्ध कराया जाए।
2. उक्त धनराशि का व्यय जलागम निदेशालय द्वारा, उक्त कार्य हेतु TERI, नई दिल्ली के Bid/price एवं कार्य से शत प्रतिशत संतुष्ट होने पर ही किया जाएगा।
3. उक्त संस्था द्वारा Final Impact Evaluation के अन्तर्गत किए गये कार्यों की विस्तृत अन्तिम रिपोर्ट यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराई जाएगी।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यक मदों हेतु ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6. मितव्ययता के फलस्वरूप अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार शासन / वित्त विभाग को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2014 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

क्रमशः....

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के "अनुदान संख्या–17" के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनागत–800–अन्य योजनाएं–97–वाह्य सहायतित योजना–02–उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना" के अन्तर्गत मानक मद '42–अन्य व्यय' के अन्तर्गत पूर्व में जलागम निदेशालय के निवर्तन पर रखी जा चुकी धनराशि के सापेक्ष किया जाएगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 284/XXVII-I/2013 दिनांक 30.3.2013 के द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनोद प्रसाद रतूड़ी)
अपर सचिव।

संख्या : 279 (1)/XIII-II/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढवाल मण्डल, पौडी।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. संबंधित संस्था।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
अनुसचिव।